छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 13 (जुलाई - सितम्बर 2020)

ईमेलः- **chhattisgarh.sccc@gmail.com** वेबसाइटः- **www.cgclimatechange.com**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. की कलम से.....

जलवायु परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी पर जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर रहा है। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी पर विभिन्न प्रभाव डाल रहा हैं। इन परिवर्तनों के कारण, पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस न्यूजलेटर के प्रकाशन में शामिल संपादक मण्डल बधाई के पात्र है। न्यूजलेटर का प्रकाशन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अद्यतन जानकारी एवं जागरूकता फैलाने में उपयोगी साधन के रूप में कार्य करेगा।

शुभकामनाओं सहित.....

(राकेश चतुर्वेदी)
आई. एफ. एस.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के त्रैमासिक समाचार पत्रिका के 13 वें अंक में आपका स्वागत है। प्रस्तुत अंक में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित/ आयोजित घटनाओं तथा कार्यक्रमों के साथ – साथ इस कार्यालय द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी भी शामिल है जिसमे प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र, रायपुर द्वारा संचालित एनएएफसीसी परियोजना का क्रियान्वयन एवं समीक्षा सम्मिलित है।

इस न्यूजलेटर के आगामी अंकों के लिए हम सभी पाठकों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करते हैं।

(ओ. पी. यादव)
आई. एफ. एस.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
एवं नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र,
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय–वस्तु

- एनएएफसीसी परियोजना ''छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का क्रियान्वयन
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा अंडर टू कोएलिशन द्वारा आयोजित आम महासभा में भाग लिया गया
- क्या आप जानते हैं ?
- पहली बार, भारत के आठ सागर तटों को प्रतिष्ठित ''ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय ईको लेबल'' दिए जाने की सिफारिश
- जी–20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भू– क्षरण और कोरल रीफ के संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत
- प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत ने 30 देशों के साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया
- अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 'नगर वन' विकसित करने हेतु शहरी वन योजना
- अग्रणी भारतीय–अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉ रतन लाल का इस वर्ष के विश्व खाद्य हेतु चयन
- समाचार शीर्षक

एनएएफसीसी परियोजना ''छत्तीसगढ़ में महानदी नदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का क्रियान्वयन

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुकूलन फंड के अंतर्गत प्रायोजित रु. 21.47 करोड़ की एक 05 वर्षीय (2016-17 से 2020-21) पायलट परियोजना ''महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' का संचालन राज्य के तीन वनमण्डलों धमतरी, बलौदाबाजार एवं महासमुंद के 19 ग्रामों में किया जा रहा है। दिनांक 15/07/2020 को NAFCC परियोजना "Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment Area in Chhattisgarh" की समीक्षा बैठक अरण्य भवन, नवा रायपुर में श्री राकेश चतुर्वेदी IFS, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, की अध्यक्षता एवं श्री ओ. पी. यादव IFS, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन) एवं नोडल अधिकारी छत्तीसगढ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की उपस्थिति में आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक में नाबार्ड, छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक श्री महेन्द्र सोरन, उपमहाप्रबंधक श्रीमति शैली जमुवार, वनमण्डल महासमुंद, धमतरी एवं बलौदाबाजार के वनमण्डलाधिकारी उपस्थित हुए।

डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, रिसर्च एसोसिएट, राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा NAFCC परियोजना पर PPT प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें उन्होंने "Climate Adaptation in Wetlands along the Mahanadi River Catchment Area in Chhattisgarh" परियोजना की विस्तार से जानकारी दी।

वनमण्डलाधिकारी महासमुंद, धमतरी एवं बलौदाबाजार द्वारा परियोजना अंतर्गत कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशु पालन विभाग, मछली पालन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर परियोजना तैयार किये जाने की जानकारी दी गई, ताकि परियोजना क्षेत्र के हितग्रहियों को लाभान्वित किया जा सके। परियोजना अंतर्गत वनमण्डलों में स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच, गली प्लग (ब्रश वुड चैक डैम), रिपेयर ऑफ ओल्ड पौंड, पाइप आउटलेट्स इन बंड्स, फील्ड बंडिंग एंड लैंड लेवलिंग, आद्र भूमियों में से गाद हटाना, परकोलेशन टैंक, कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप डैम एवं चैक डैम आदि कार्यों को कराया जा रहा है।

श्री महेन्द्र सोरन, निदेशक महाप्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुए शेष कार्यों को मार्च 2021 तक पूर्ण किये जाने का आहवान किया।

नोडल अधिकारी द्वारा तीनो वनमण्डलों में परियोजना अंतर्गत शेष बचे कार्यों को संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये, ताकि परियोजना लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकें।

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा अंडर टू कोएलिशन द्वारा आयोजित आम महासभा में भाग लिया गया

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा अंडर टू कोएलिशन द्वारा आयोजित आम महासभा में भाग लिया गया, जो कि जलवायु सप्ताह NYC 2020 के साथ ऑनलाइन माध्यम से 21–27 सितंबर के बीच आयोजित किया गया, जो कि संयुक्त राष्ट्र और न्यूयॉर्क शहर द्वारा समर्थित था और क्लाइमेट ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया, जिसमे ''सिर्फ परिवर्तन के माध्यम से'' शून्य कार्बन उत्सर्जन भविष्य की ओर खोज जारी है। जलवायु सप्ताह NYC 2020 में भारत, इक्वाडोर और ऑस्ट्रेलिया सहित देशों द्वारा 500 से अधिक कार्यक्रम हुए, और 1,500 से लोग अधिक उपस्थित थे।

क्लाइमेट ग्रुप के सीईओ हेलेन क्लार्कसन ने एक बयान में कहा, ''वर्चुअल दुनिया की जलवायु परिवर्तन की दिशा में उपलब्धता और जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका है।'' साथ ही उन्होंने कहा कि ''हम एक मॉडल का निर्माण करना चाहते हैं जो हमें इसे जारी रखने की अनुमति दे तब भी जब हम फिर से एक साथ आने में सक्षम हों।''

The Climate Group's programmes to help industry to lead the transformation on the ground में चर्चा के दौरान दिव्या शर्मा, द क्लाइमेट ग्रुप्स इंडिया के संचालन के कार्यकारी निदेशक ने कहा कि यह प्रयास ''ऊर्जा और उत्पादकता गति के लिए प्रतिबद्ध'' कंपनियों की मदद कर रहा था। शर्मा ने तर्क दिया कि अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों को प्रभावित करने की क्षमता है।

पहली बार, भारत के आठ सागर तटों को प्रतिष्ठित ''ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय ईको लेबल'' दिए जाने की सिफारिश

अंतरराष्ट्रीय सागर तट स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने एक आभासी कार्यक्रम में घोषणा की कि पहली बार भारत के आठ सागर तटों की प्रतिष्ठित ''अंतरराष्ट्रीय ईको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र'' के लिए सिफारिश की गई है ।

प्रमुख पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्यूरी ने यह सिफारिश की है। ''ब्लू फ्लैग सागर तट'' विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। ये आठ सागर तट हैं –गुजरात का शिवराजपुर तट, दमण एवं दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड बीच और पदुबिरदी बीच, केरल का कप्पड बीच, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा बीच, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच।

जी–20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भू– क्षरण और कोरल रीफ के संरक्षण कार्यक्रम के वैश्विक पहल की शुरुआत

सऊदी अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में जी–20 देशों की पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक (ईएमएम) दिनांक 16 सितम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, भारत ने पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा के साथ–साथ प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

श्री जावडेकर ने कहा, भारत एक बेहतर दुनिया के लिए जी 20 देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, भारत के पास विशाल जैव–विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा, भारत कोरल रीफ संरक्षण बढ़ाने के लिए उपाय कर रहा है। श्री जावडेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के कदम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने और ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने होंगे।

क्या आप जानते हैं ?

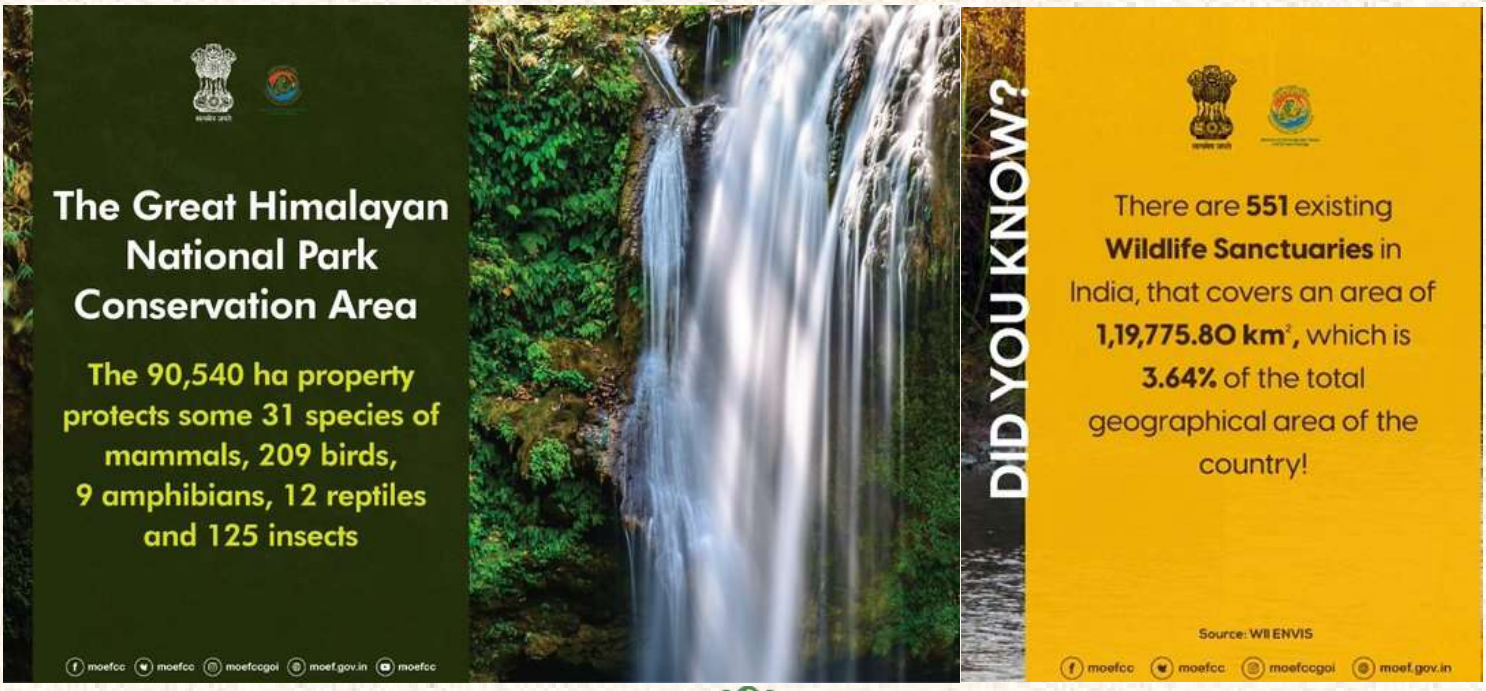

प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत ने 30 देशों के साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया

पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के ग्यारहवें सत्र में भारत ने 30 अन्य देशों के साथ सामूहिक लचीलेपन को संवर्धित करने और जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को उत्प्रेरित करते हुए तथा विशेष तौर पर असहाय लोगों की भी सहायता करते हुए कोविड–19 के बाद अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में नई जान डालने की चुनौती से निपटने के तरीकों और साधनों पर विचार–विमर्श किया।

प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह समूचा विश्व एकजुट होकर नोवल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तलाशने में जुटा है, उसी तरह पर्यावरण संबंधी प्रौद्योगिकी हमारे पास मुक्त स्रोत के रूप में होनी चाहिए, जिसे किफायती दाम पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जलवायु वित्त के मामले पर जोर देते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि विश्व को अब और ज्यादा की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमें विकासशील विश्व को तत्काल प्रभाव से 1 ट्रिलियन डॉलर अनुदान देने की योजना तैयार करनी चाहिए।"

कोविड–19 महामारी का मुकाबला कर रहे विश्व के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार कोविड–19 ने हमें यह पाठ पढ़ाया है कि हमारा थोड़े में भी गुजारा हो सकता है। पर्यावरण मंत्री ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि विश्व को सतत जीवन शैलियों की आवश्यकता के अनुरूप उपभोग की ज्यादा टिकाऊ परिपाटियों को अपनाने पर विचार करना चाहिए, जिनका प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस सीओपी ने प्रस्तुत किया था।

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की 10 साल की समय–सीमा महत्वाकांक्षी है और वह पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्य के अनुरूप भी है। श्री जावड़ेकर ने विश्व के सामने मौजूद नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में तेजी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल नए रोजगारों को सृजित करने के अवसर के बारे में भी चर्चा की।

यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद, पीटरबर्ग जलवायु संवाद का ग्यारहवां सत्र था, जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्रवाई की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च–स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही है। वर्चुअल ग्यारहवें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद की सह–अध्यक्षता जर्मनी और ब्रिटेन द्वारा की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के लिए 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 26) का आगामी अध्यक्ष है। संवाद में लगभग 30 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 'नगर वन' विकसित करने हेतु शहरी वन योजना

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरकार ने वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स और स्थानीय नागरिकों के बीच भागीदारी और सहयोग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए अगले पांच वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) हर साल 5 जून को मनाया जाता है। (यूएनईपी) द्वारा घोषित थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए डब्ल्यूईडी मनाता है इस वर्ष का विषय जैव विविधता है। कोविड–19 महामारी के कारण हालात के मद्देनजर मंत्रालय ने इस वर्ष के थीम नगर वन (शहरी वन) पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया।

शहरी वनों पर सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक विवरणिका का विमोचन और नगर वन योजना की घोषणा करते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ये वन शहरों के फेफड़ों के रूप में काम करेंगे और मुख्य रूप से शहर की वन भूमि पर या स्थानीय शहरी निकायों द्वारा प्रस्तावित किसी अन्य खाली जगह पर होंगे। इस वर्ष के थीम अर्थात जैव विविधता पर विशेष ध्यान देने के साथ ''टाइम फॉर नेचर'' पर जोर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा, ''प्रधान नियम यह है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं, तो प्रकृति हमारी रक्षा करती है''। इस वर्ष के फोकस जैव विविधता पर जोर देते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा, ''भारत में दुनिया का केवल 2.5 प्रतिशत भूखंड होने, उस पर मानव आबादी का 16 प्रतिशत होने के साथ–साथ मवेशियों की आबादी और केवल 4 प्रतिशत ताजा जल स्रोत होने जैसे अनेक अवरोधों के बावजूद, दुनिया की 8 प्रतिशत जैव विविधता विद्यमान है ये हमारे पास जो विशाल जैव विविधता है, वह प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने वाले भारतीय लोकाचारों का परिणाम है।''

भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि ''भारत संभवतः एकमात्र ऐसा देश है जहां पेड़ों की पूजा की जाती है, जहां जानवरों, पक्षियों और सरीसृपों की पूजा की जाती है और यह पर्यावरण के लिए भारतीय समाज का सम्मान है। उन्होंने कहा कि हमारे पास युगों से गांव के जंगल की बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा हुआ करती थी, अब शहरी वन संबंधी इस नई योजना से इस खाई को भरा जा सकेगा क्योंकि शहरी क्षेत्रों में उद्यान तो हैं लेकिन जंगल बहुत ही कम हैं ये शहरी वन बनाने की इस गतिविधि के साथ हम अतिरिक्त कार्बन सिंक भी तैयार करेंगे।''

यूएनसीसीडी के कार्यकारी निदेशक, श्री थियाव ने कहा कि ''क्या अब समय नहीं आ गया है कि हमें इस बात का एहसास हो कि यदि प्रकृति को हमारी जरूरत है भी, तो भी उससे कहीं ज्यादा हमें प्रकृति की जरूरत है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हममें इतनी विनम्रता हो कि हम प्रकृति के साथ अपने संबंधों के बारे में नए सिरे से सोचे और उन्हें पुनर्परिभाषित करें। शायद अब समय आ गया है कि मानवता प्रकृति के लिए एक नया सामाजिक अनुबंध करे।''

अग्रणी भारतीय–अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉ रतन लाल का इस वर्ष के विश्व खाद्य हेतु चयन

अग्रणी भारतीय–अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉ रतन लाल का इस वर्ष के विश्व खाद्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चयन किया गया है, जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक मिट्टी–केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्यधारा में लाने के लिए प्रदान किया गया है ।

विश्व खाद्य पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, और प्राप्तकर्ता को खाद्य की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार के लिए $ 250,000 प्रदान किए जाते हैं।

मृदा संरक्षण में डॉ लाल के योगदान ने छोटे किसानों को उनकी मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करके वैश्विक खाद्य आपूर्ति में वृद्धि की है।

विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन की अध्यक्ष बारबरा स्टिन्सन ने वाशिंगटन डीसी में एक ऑनलाइन समारोह में विजेता के रूप में डॉ लाल की घोषणा की। इस समारोह में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और अमेरिकी कृषि सचिव सन्नी पेर्ड्यू की पूर्व–रिकॉर्ड की गई टिप्पणी थी।

वे पृथ्वी के अनुमानित 500 मिलियन छोटे किसानों की मदद कर रहे है जो बेहतर प्रबंधन, कम मिट्टी की गिरावट और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से अपनी भूमि के वफादार प्रबंधक हैं। सचिव सन्नी पेर्ड्यू ने कहा ''जो लोग इन खेतों पर निर्भर हैं उनको इसने काम से बहुत फायदा होगा।''

मृदा संरक्षण में अपने काम को आगे बढ़ाते हुए, फाउंडेशन के अध्यक्ष ने कहा, ''डॉ लाल एक इन्नोवेटर हैं, इनमे मृदा विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक अद्भुत जुनून है, इनके द्वारा किया गया अनुसंधान मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, कृषि उत्पादन को बढ़ाता है, भोजन के पोषण की गुणवत्ता में सुधार करता है, पर्यावरण को पुर्नस्थापित करता है और जलवायु परिवर्तन को कम करता है। ''

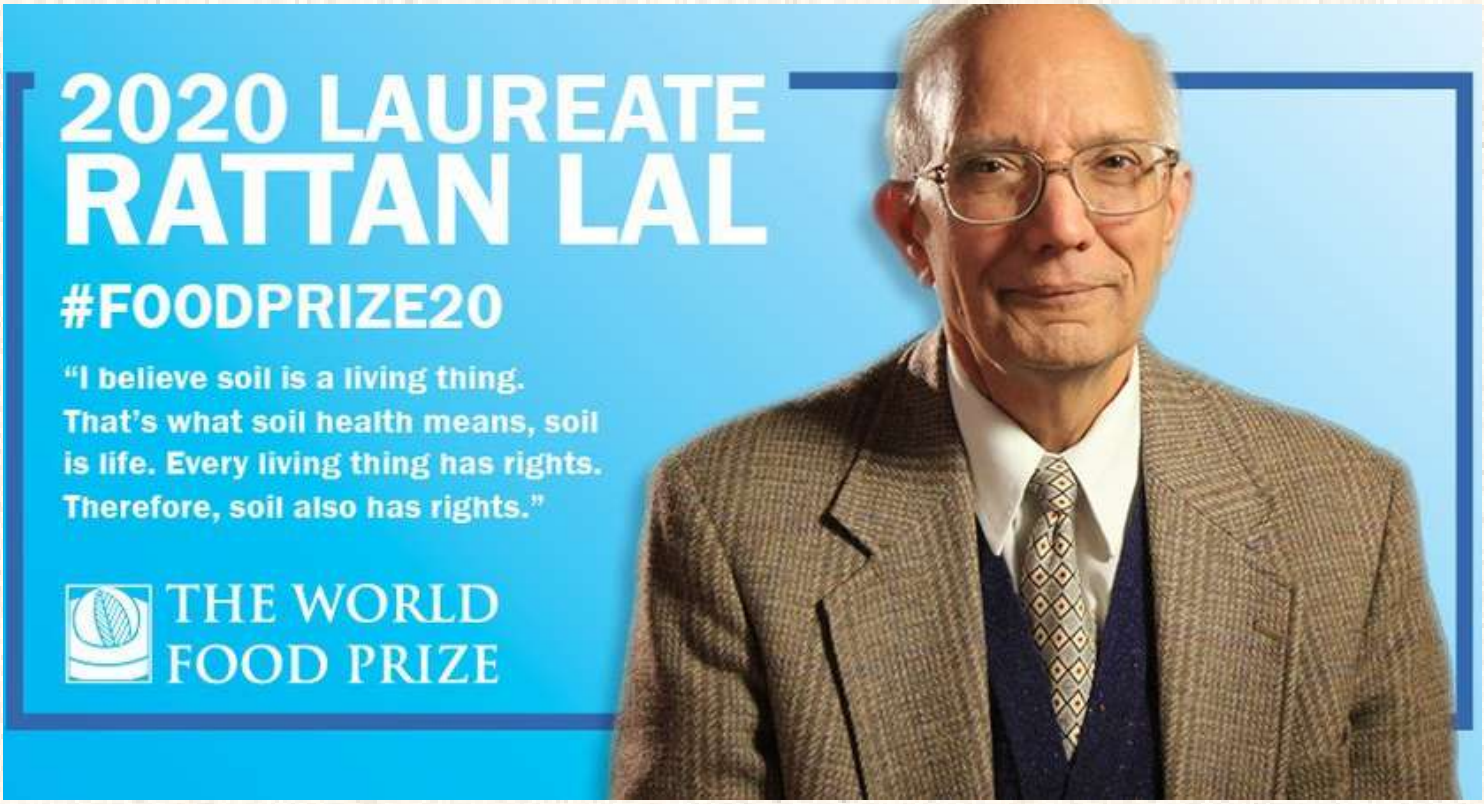

समाचार शीर्षक

वर्ल्ड एन्वायरमेंट डे पर पढ़िए शहर के बेस्ट ग्रीन जोन पर खास रिपोर्ट

ऑक्सीजोन से शहर को मिले नए लंग्स, 5 हजार पेड़ों से घिरा ये जोन दस हजार जिंदगियों को दे रहा सांसें

- एक पेड़ सालभर में 260 पाउंड ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ से औसतन दो लोगों को मिलती है पर्याप्त ऑक्सीजन
- इस लिहाज से 19 एकड़ में फैले ऑक्सीजोन के पांच हजार पेड़ों से दस हजार लोगों को मिल रही ऑक्सीजन

सिटी रिपोर्टर . रायपुर

ये तस्वीर है शहर के बीचों-बीच बनाए गए ऑक्सीजोन की। तीन साल पहले कलेक्ट्रेट कैंपस के पीछे लगभग 19 एकड़ में 12 करोड़ की लागत से डेवलप किए गए इस मानव निर्मित जंगल को बनाने के लिए कई दुकानों को तोड़ा गया था। तब इसका भारी विरोध हुआ था, लेकिन अब यही जोन शहर के लंग्स बन चुके हैं। पांच हजार से ज्यादा पेड़ों से घिरे इस जोन में लॉकडाउन से पहले रोजाना लगभग दो हजार लोग मॉर्निंग और ईवनिंग वॉक करने आते थे। यहां अधिकतर ऐसे पेड़ हैं, जिनसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है। ऐसी ग्रीनरी शहर के बीचों-बीच कहीं भी नहीं है।

- यहां चारों ओर पाथवे बनाया गया है।
- यहां मेडिटेशन जोन और वॉर्मअप स्पेस भी है।
- हर उम्र के लोगों के लिए ओपन जिम और बच्चों के लिए चिल्ड्रन जोन भी है।
- प्राकृतिक सौंदर्य का अहसास कराने के मकसद से यहां कृत्रिम तालाब भी बनाया गया है।

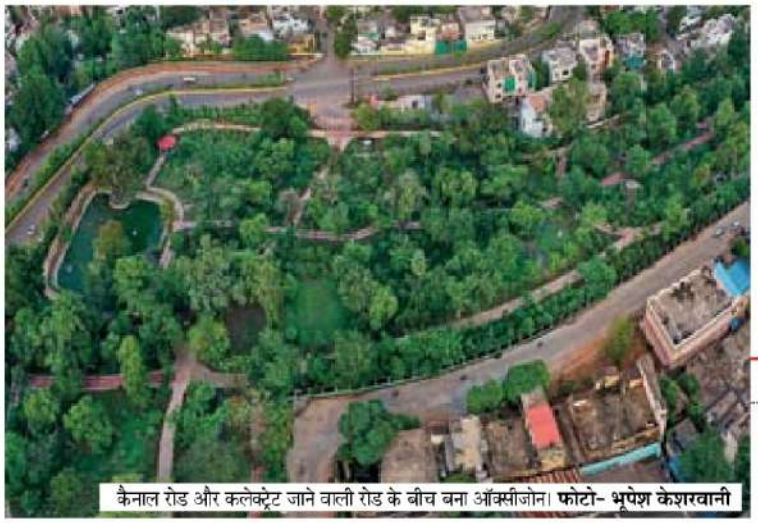

कैनाल रोड और कलेक्ट्रेट जाने वाली रोड के बीच बना ऑक्सीजोन। फोटो- भूपेश केशरवानी

- जल: केंद्रीय भू-जल की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर का जल स्तर 2019 में 20 मीटर नीचे जा चुका था। लेकिन लॉकडाउन के कारण इस साल जल स्तर गिरने के बजाय 20 मीटर ही रहने का अनुमान है।
- हवा: लॉक डाउन से पहले PM 10 यानी हवा में धूल के बड़े कणों की मात्रा औसतन 110 माइक्रो ग्राम क्यूबिक मीटर थी, ये अब 60 माइक्रो ग्राम क्यूबिक मीटर रह गई है।
(PM 10 का स्तर 100 माइक्रो ग्राम क्यूबिक मीटर से कम सामान्य और 100 से ज्यादा होने पर सेहत के लिए नुकसानदेह माना जाता है।)
- ध्वनि: लॉकडाउन से पहले शहर में ध्वनि प्रदूषण लगभग 65 डेसिबल था, ये अब लगभग 47 डेसिबल है। मानक स्तर 45 डेसिबल है।

7 एकड़ में बना रहे सेकेंड फेज

- ऑक्सीजोन के दूसरे फेज का लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इस माह के आखिर तक होगा तैयार
- उस इलाके के आसपास रहने वाले लगभग 10 हजार लोग भी ऑक्सीजोन से सीधे जुड़ सकेंगे।

DB स्टार RAIPUR | TUESDAY FOCUS 02 JUNE | 2020

5 जून विश्व पर्यावरण दिवस: तूफान और बढ़ती गर्मी वैज्ञानिकों में चिंता का विषय

क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, तय समय से पहले ही बनने लगे तूफान

कोरोना संकट के बीच पर्यावरण जरूर साफ हुआ है, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण और मानवीय क्रियाकलापों ने वैश्विक जलवायु पर काफी विपरीत प्रभाव डाला है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर वैज्ञानिकों के बीच यह गंभीर चिंता का विषय है कि तूफान, बढ़ती गर्मी जैसी बदलती जलवायु परिस्थितियां इस वर्ष और आने वाले समय में अधिक घातक हो सकती है।

एक भी बूंद पानी व्यर्थ न करने वाला प्लांट बनेगा, भिलाई में प्रोजेक्ट शुरू

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र एक भी बूंद पानी व्यर्थ नहीं बहाने वाला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) का पहला संयंत्र होगा। इसके लिए संयंत्र प्रबंधन 3 करोड़ के डिलिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।

सम्पादक मंडल

- श्री ओ. पी. यादव (मुख्य संपादक)
- श्री राकेश श्रीवास
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- श्री अभिनव अग्रहरि

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ
अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19
नवा रायपुर, छत्तीसगढ
फोन : 0771 – 2512808
ईमेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgclimatechange.com